भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2555

जिसका उत्तर 22 दिसंबर, 2022 को दिया जाना है।

.....

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

2555. श्री विनसेंट एच. पाला:

डॉ. अमर सिंह:

डॉ. ए. चेल्लाकुमार:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की कार्यकारी समिति की उस रिपोर्ट का संज्ञान लिया है जिसमें गंगा बेसिन के प्रबंधन के लिए यूरोपीय और अमेरिका आधारित मॉडलों पर विचार करने की बात की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात से अवगत है कि एनएमसीजी ने पहले गंगा कार्यक्रम के लिए विदेशी नदी सफाई मॉडल का अनुसरण न करने की सलाह दी थी, जिसका कारण भारतीय नदियों की वर्षा आधारित प्रकृति और उनके जल पर लाखों लोगों की निर्भरता सहित अन्य कारक थे और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यमान नदी प्रबंधन रणनीतियों के बदले उक्त विदेशी मॉडल पर विचार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्तिराज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की कार्यकारी समिति (ईसी) ने दिनांक 13 जुलाई, 2022 को आयोजित अपनी 43$^{वीं}$ बैठक में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) को "एनजीपी और भारतीय नदियों के लिए यूरोपीय नदी कायाकल्प अनुभव कितना प्रासंगिक है" पर एक परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना 14 दिसंबर, 2021 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के उद्देश्यों के अनुसार विकसित की गई थी। प्रस्ताव के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

i. यूरोप और भारत (एनजीपी) के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान के फोकस क्षेत्रों का दायरा और पहचान।

ii. यूरोप और भारत के बीच संस्थागत अनुसंधान और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए सीपीआर-एनएमसीजी सहयोगात्मक कार्यक्रम लागू करना।

वर्तमान में सीपीआर में अध्ययन चल रहा है।

(ख) से (घ): एनएमसीजी द्वारा कार्यान्वित नमामि गंगे परियोजना सात आईआईटी के संघ द्वारा तैयार गंगा नदी बेसिन प्रबंधन योजना पर आधारित है। नमामि गंगे के तहत विभिन्न सीवरेज परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपनाई गई प्रौद्योगिकियां आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन के दिशानिर्देशों पर आधारित हैं। हालाँकि, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने नदी पुनर्जीवन के मॉडल पर ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए जर्मनी, नीदरलैंड, इज़राइल, डेनमार्क, जापान आदि जैसे कई देशों के साथ समझौता ज्ञापन किया है। सीपीआर के उपरोक्त अनुसंधान उन्मुख अध्ययन के कार्यान्वयन द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) यूरोपीय संस्थानों के साथ सहयोगी ज्ञान विनिमय कार्यक्रमों के लिए अग्रणी व्यापक नीति और संस्थागत पहलुओं से नदियों के कायाकल्प में यूरोपीय अनुभवों से सीख का विश्लेषण करना चाहता है।

*****